IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

वर्तमान परिवेश में आत्मनिर्भर भारत अभियान – एक मूल्यांकन

डॉ ब्रजेश श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर – अर्थशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय, मानिकपुर चित्रकूट

शोध सारांश

आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने आप को पूर्ण करने की क्षमता और निर्भरता पर प्रतिबंध नहीं। यह व्यक्ति के जीवन में आत्म-निर्भर बनने की भावना का मूल है, जो हमारे समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता से हमें कोई भी प्रेरणा मिलती है और हम भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। भारत सरकार ने "आत्मनिर्भर भारत" अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देना है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और हमारी कंपनियों पर विज्ञापन कम होते जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें शिक्षा, कौशल विकास और परिश्रम पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, तो हम नए अवसरों को पहचानते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, आत्मनिर्भरता के लिए केवल व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता है बल्कि यह देश के विकास की भी कुंजी है। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह समाज में अपना योगदान दे सके।

मुख्य शब्द – आत्मनिर्भरता , विकास , स्वदेशी ,रोजगार

प्रस्तावना

मई 2020 में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाजारों में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की घोषणा महामारी के बीच की गई थी, जब सरकार ने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपये (268.74 अरब अमेरिकी डॉलर) की धनराशि आवंटित की, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। इसमें 'स्थानीय से वैश्विक', 'विश्व के लिए निर्मित' और 'स्थानीय के लिए मुखर' जैसे विषय शामिल हैं।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 1, October 2022 Impact Factor: 6.252

• भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में विकसित करना।

• निजी क्षेत्र की क्षमताओं और संभावनाओं में सरकार का विश्वास बढ़ाना।

• भारतीय निर्माताओं के लिए 'सकारात्मक शक्ति गुणक' स्थापित करना।

• कृषि, वस्त्र, परिधान और आभूषण सहित वस्तुओं के निर्यात के लिए वैश्विक बाजारों में प्रवेश करना।

• आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वित्त वर्ष 2022 के बजट की सहायता से प्रत्येक क्षेत्र (जैसे रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना आदि) की पर्याप्तता का निर्धारण करना।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता

वित्त वर्ष 2024 में औद्योगिक क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में वार्षिक आधार पर 11.89% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मूल धातु, मोटर वाहन और रसायन क्षेत्रों में क्रमशः 11.56%, 9.11% और 8.81% की मजबूत वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2020 में, एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट में 40 उप-क्षेत्रों (जैसे कृषि आधारित उत्पाद, औषधि निर्माण, रसायन, ऑटोमोबाइल घटक, हस्तशिल्प, सौंदर्य प्रसाधन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स) की पहचान की गई, जिनका चीन से लगभग 33.6 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के घरेलू विनिर्माण में अतिरिक्त निवेश के बिना चीन से कुल आयात के 25% (जीडीपी के लगभग 0.3% की बचत) को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है। इसमें यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022 में, देश दवा निर्माण, रसायन, ऑटोमोबाइल घटक, हस्तशिल्प, सौंदर्य प्रसाधन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों से आयात को प्रतिस्थापित करके चीन के साथ 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे को कम कर सकता है।

आत्मनिर्भर भारत के लाभ (आत्मनिर्भर भारत अभियान)

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2021 से कई उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना है-

प्राथमिक क्षेत्र	इस क्षेत्र में कृषि, खनन और मत्स्य पालन तीन प्रमुख उद्योग हैं।
द्वितीयक क्षेत्र	इस क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, उपयोगिताएँ, लघु, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और कुटीर उद्योग जैसे उद्योग शामिल हैं।
तृतीयक क्षेत्र	इस क्षेत्र में खुदरा, पर्यटन, बैंकिंग, रियल एस्टेट, मीडिया और मनोरंजन, दूरसंचार से लेकर आतिथ्य और अवकाश तथा सूचना प्रौद्योगिकी तक की प्रमुख सेवाएं शामिल हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

चतुर्धातुक क्षेत्र	इस क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग शामिल हैं।

यह मिशन निम्नलिखित चार प्रमुख कारकों पर केंद्रित है - भूमि, श्रम, तरलता और कानून। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 2014 और 2020 के बीच देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करने के लिए कई पहलें शुरू कीं।

प्रमुख कारक	**आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा (2014 से 2020 के बीच) की गई पहल।**
भूमि और श्रम	देश के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने जन धन खाते, आयुष्मान भारत योजना, सूक्ष्म बीमा योजनाएं, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) आधारित सुधार, पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना सहित कई योजनाएं शुरू कीं।
	किसानों को सशक्त बनाने और भूमि की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाएं शुरू कीं और एक नया मत्स्य विभाग स्थापित किया।
तरलता	कारोबारी माहौल को मजबूत करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय, जीएसटी सुधार, एफडीआई सुधार और कारोबार में आसानी से संबंधित सुधार जैसी पहल शुरू कीं।
कानून	निवेश को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने कई नीतिगत सुधार लागू किए (जिनमें हवाई अड्डों का निजीकरण, बिजली क्षेत्र में सुधार और खनन क्षेत्र का शुद्धिकरण शामिल हैं), जैसे कि निवेश आकर्षण के आधार पर राज्यों को सूचीबद्ध करना, सौर पीवी और उन्नत बैटरी निर्माण सेल जैसे अग्रणी क्षेत्रों को बढ़ावा देना।

इस मिशन के प्रमुख लाभार्थियों में श्रमिक (मजदूर), किसान, दिहाड़ी मजदूर (जो देश के विकास में योगदान देते हैं), सरकार को आयकर देने वाले मध्यम वर्ग के लोग और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले उच्च वर्ग के लोग शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान: प्रमुख पहल और प्रगति

सरकार ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज (एएनबी 1.0) की घोषणा की और प्रगति को बनाए रखने के लिए 2020 के अंत में दो अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज (एएनबी 2.0 और एएनबी 3.0) शुरू किए। आरबीआई की पहलों सहित कुल आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का अनुमान लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपये (362.49 अरब अमेरिकी डॉलर) था, जो जीडीपी का 13% से अधिक है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत, सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की पुनर्परिभाषा, खनिज क्षेत्र का व्यवसायीकरण, कृषि और श्रम सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं जैसे संरचनात्मक सुधारों को सुगम बनाया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, सरकार ने निम्नलिखित योजनाएँ लागू कीं -

• **उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू की गई** - भारत के विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत, सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये (27.02 अरब अमेरिकी डॉलर) के बजट से 14 क्षेत्रों में उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू की।

आवंटित बजट पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजनाओं के लिए निर्धारित 40,951 करोड़ रुपये (5.45 अरब अमेरिकी डॉलर) की अतिरिक्त राशि है। इसके अतिरिक्त, इन पीएलआई योजनाओं ने विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। उदाहरण के लिए, फरवरी 2021 में, अमेज़न ने भारत में अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की; मार्च 2021 में, एप्पल ने भारत में आईफोन 12 की असेंबली शुरू की।

• **स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को सुदृढ़ करना** - केंद्रीय बजट 2021-22 में, सरकार ने एक नई केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है जिसे देश की स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए अगले छह वर्षों में लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (पीएमएएनएसवाई) के तहत, सरकार ने मौजूदा 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' को मजबूत करने और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए छह वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये (8.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की धनराशि आवंटित की है ताकि नई और उभरती बीमारियों का पता लगाया जा सके और उनका इलाज किया जा सके।

• **महिला उद्यमिता पर अधिक ध्यान** - 2015-16 में, सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की 'महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' योजना के तहत महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यूटीपी) कार्यक्रम शुरू किए, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। पिछले पांच वर्षों में (मार्च 2021 तक), लगभग 10,000 ग्रामीण महिलाओं को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ है, 28 जल संग्रहण संयंत्र सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और देश भर में 12 पार्क निर्माणाधीन हैं।

• **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना** - आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां शुरू कीं। उदाहरण के लिए, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया, 101 सैन्य वस्तुओं पर 'आयात प्रतिबंध' लगाया और रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 लागू की। रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) ने अपने 300वें अनुबंध को अंतिम रूप देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह अनुबंध अत्याधुनिक गैलियम नाइट्राइड

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 1, October 2022 Impact Factor: 6.252

सेमीकंडक्टरों के डिजाइन और विकास से संबंधित है, जो रडार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (ईडब्ल्यू) जैमर तक रक्षा अनुप्रयोगों में वायरलेस ट्रांसमीटरों के आगामी युग के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया है, जिसमें घरेलू उत्पादन 2 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपये (33.79 अरब अमेरिकी डॉलर) का उत्पादन हासिल करना और खुद को एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 (डीपीईपीपी 2020) में 1.75 लाख करोड़ रुपये (25 अरब अमेरिकी डॉलर) के कुल राजस्व, जिसमें निर्यात भी शामिल है, को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं में 35 हजार करोड़ रुपये (5 अरब अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को Su-30MKI विमान के लिए 240 AL-31FP एयरो इंजन के लिए 26,000 करोड़ रुपये (3.12 अरब अमेरिकी डॉलर) से अधिक का अनुबंध दिया है। एचएएल का कोरापुट प्रभाग इन इंजनों का निर्माण करेगा, जिससे भारत की रक्षा तैयारियों को बल मिलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों और उद्योगों को शामिल किया जाएगा और 63% स्थानीय सामग्री का लक्ष्य रखा गया है। आपूर्ति आठ वर्षों में की जाएगी, जिसमें प्रति वर्ष 30 इंजन दिए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय वायु सेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सूट और संशोधन किट के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2,385 करोड़ रुपये (277 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का अनुबंध किया है।

• आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उन्नत बनाने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु 'पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएमएफएमई)' योजना शुरू की है। सरकार ने इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये (1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का फंड आवंटित किया है, जिसे वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2025 के बीच लागू किया जाएगा।

प्रमुख उपलब्धियां

आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

• इस मिशन ने एयर कंडीशनर के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद की है, क्योंकि अक्टूबर 2020 से नवंबर 2020 के बीच भारत में स्प्लिट एसी या एयर कंडीशनर के आयात में 65% की कमी दर्ज की गई; यह सरकार की आत्मनिर्भरता की नीति 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के लिए एक अच्छा संकेत है। अक्टूबर 2020 में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने रेफ्रिजरेंट वाले एयर कंडीशनर के आयात को प्रतिबंधित करने वाला एक नियम जारी किया।

• मिशन के शुभारंभ के 60 दिनों के भीतर, भारत के घरेलू उत्पादक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किटों की एक स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में सक्षम हो गए, जिससे पीपीई किटों में देश की आत्मनिर्भरता प्रदर्शित हुई।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 2, Issue 1, October 2022
Impact Factor: 6.252

• जनवरी 2020 में, देश ने दो 'मेड इन इंडिया' टीकों - कोवैक्सिन और कोविशील्ड - के साथ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया और आत्मनिर्भर बनने के अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया।

- घरेलू आपूर्ति: 14 अप्रैल, 2021 तक, भारत का संचयी टीकाकरण कवरेज 11 करोड़ से अधिक हो गया।

- अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति: 15 अप्रैल, 2021 तक, देश ने 90 से अधिक देशों को लगभग 65.5 मिलियन स्वदेशी कोविड-19 टीके निर्यात किए।

निष्कर्ष

हाल ही में सरकार द्वारा किए गए सुधार, जैसे प्रमुख उद्योगों में निजी कंपनियों को संचालन की अनुमति देना, कृषि संबंधी पहल और श्रम सुधार लागू करना तथा वाणिज्यिक कोयला खनन को सक्षम बनाना, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनने के अपार अवसर प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, विनिर्माण क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बजट में किए गए पर्याप्त प्रोत्साहन तथा सहायक सार्वजनिक स्वतंत्रता नीति सुधारों से घरेलू विनिर्माण कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी कंपनियों को देश में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा सकेगा; जिससे भारत आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर होगा।

सन्दर्भ सूची

[1]. aatmnirbharsena-org

[2]. Presentation made by Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt- Nirmala Sitharaman under Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan to support Indian economy in fight against COVID&19 Ministry of Finance May 13 2020PRS-

[3]. https//static-pib-gov-

[4]. www.google.com

[5]. www.wikipedia.com